यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/01/2020 **दिनांक** : 02.01.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

अलविदा 2019 – स्वागत 2020

नववर्ष के अवसर पर एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 28/163/2020/1 दिनांक 1.1.2020 जारी किया गया है जिसका अनूदित सार सभी इकाईओं तथा सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

अलविदा 2019 – स्वागत 2020

हम इस नववर्ष पर अपनी सभी यूनियनों तथा सदस्यों को अपनी शुभकामनायें और अभिवादन व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाला वर्ष विगत वर्ष की तुलना में बेहतर और खुशहाल होगा।

जब हम वर्ष को अलविदा कहते हैं जो गुजर गया है, तो हम कामगार वर्ग और आम जनता द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा में और उनके अस्तित्व, जीविका और निर्वाह पर हमलों के विरूद्ध दुनिया भर में जारी संघर्षों को याद करते हैं। इन संघर्षों ने कुछ हद तक हमलों को पीछे धकेलने में उनकी मदद की है।

लगातार रहना, चिंता का विषय है : हमारे देश में, भाजपा संसद में बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व के साथ दूसरे सत्र के लिए सत्ता में वापस आई। इसने उन्हें संबंधित वर्ग से लोकतांत्रिक विरोध से बेपरवाह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की अपनी कार्यसूची को आगे बढ़ाने के लिए अधिक अधिकार और क्षमता प्रदान की है। परिणाम सभी को मालूम हैं, जिसमें लोगों के कई वर्ग असंतुष्ट हैं और देश के कई हिस्से अशांत हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करेगी और बड़े पैमाने पर लोगों को साथ लेकर चीजों को करने का एक अधिक संतुलित तरीका अपनाएगी।

भारत के 1% अमीरों का 73% धन उत्पादन पर एकाधिकार है : एक नए सर्वेक्षण ने दर्शाया है कि, भारत में 1% अमीरों ने पिछले साल देश में उत्पन्न 73% धन पर एकाधिकार कर लिया, जो बढ़ती आय

जारी पृष्ठ 2

असमानता की एक चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह ऑक्सफैम द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार, जनसंख्या के सबसे गरीब आधे हिस्से में शामिल 67 करोड़ भारतीयों ने अपनी संपत्ति में केवल 1% की वृद्धि देखी।

वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 102वें नम्बर पर है : पिछले माह जारी वैश्विक भूख सूचकांक ने 117 देशों में से भारत को 102वें स्थान पर रखा है और हमारे देश की दक्षिण एशियाई देशों में सबसे कम रैंकिंग है। यूनिसेफ ने अपनी वर्ल्डस चिल्ड्रेन 2019 रिपोर्ट में बताया है कि भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की 69% मौत कुपोषण के कारण होती है। इसने आगे कहा कि भारत में पांच वर्ष की आयु का हर दूसरा बच्चा किसी न किसी रूप में कुपोषण से प्रभावित है। सरकार द्वारा उठाए गए गरीबी–विरोधी सुदृढ़ उपायों से ही गरीबी और भूख का अंत हो सकता है और भारत को भूख–मुक्त बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार की अन्य प्राथमिकतायें दिखाई पड़ती हैं।

भारत में दुनिया के 31% गरीब बच्चे हैं : ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (ओपीएचआई) की एक रिपोर्ट में, जो गरीबी उन्मूलन परियोजना है, कहा गया है कि विश्व के 689 मिलियन गरीब बच्चों में से, लगभग 31% भारत में रहते हैं जो नाइजीरिया, इथियोपिया और पाकिस्तान की तुलना में बहुत अधिक है।

अर्थव्यवस्था जर्जर हालत में है : आर्थिक मोर्चे में, यह गंभीर चिंता का विषय है कि अर्थव्यवस्था के सामने पीछे हटने की चुनौती है। मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है, बेरोजगारी अभूतपूर्व है, निर्माण क्षेत्र मंदी से पीड़ित है, औद्योगिक उत्पादन लड़खड़ा रहा है और कृषि क्षेत्र गंभीर संकट में है।

सरकार की दवा काम नहीं करेगी : इसके परिणामस्वरूप, जीडीपी गिर रही है। सरकार दावा करती है कि यह 4.5 है, अरविंद सुब्रमण्यम कहते हैं कि यह 2.5 है, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि यह 1.5 है। जो भी हो, तस्वीर निराशाजनक है और सरकार अनभिज्ञ दिखाई पड़ती है। पेरासिटामोल की उनकी खुराक अर्थव्यवस्था में रोग का उपचार करने वाली नहीं है। स्पष्ट रूप से समस्या संरचनात्मक है लेकिन सरकार यह मानना चाहती है कि यह चक्रीय है और इसलिए यह उचित समय में ठीक हो जायेगा।

धन का सृजन कौन कर रहा है ? संकेत स्पष्ट हैं कि अर्थव्यवस्था कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट्स और व्यावसायिक घरानों की पकड़ में जा रही है जिन्हें तमाम रियायतें दी जा रही हैं। यह पक्षपात तथा और भी असमानता पैदा कर रहा है। सुधारात्मक उपाय करने के बजाय, सरकार आश्चर्यजनक रूप से यह तर्क दे रही है कि इन ''धन सृजनकर्ताओं'' को और अधिक संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन हर कोई जानता है कि वे धन के लूटेरे हैं।

कामगार वास्तविक धन सृजनकर्ता हैं लेकिन उनके उचित हिस्से के लिए उनक न्यायसंगत दावा नकारा और वंचित किया जा रहा है। सरकार की नीति ''व्यापार करने में आसानी'' प्रदान करना है लेकिन परिणाम नौकरो समाप्त करने में आसानी है। पहले यह नौकरी उन्मुख वृद्धि थी, फिर यह बेरोजगार वृद्धि हुई और अब यह नौकरी की हानि है और वृद्धि नहीं है ! ये स्पष्ट रूप से अर्थव्यवस्था को बेतहाशा उदार बनाने और अर्थव्यवस्था को ''बाजार की ताकतों'' के लिए छोड़ने का परिणाम है।

जारी पृष्ठ 3

कथित श्रम सुधार – खतरे का संकेत : जबकि कामगार इन कामगार–विरोधी नीतियों का विरोध करना चाहते हैं, तो सरकार हमारे श्रम अधिकारों का छीन लेना चाहती है। सभी श्रम कानूनों को नियोक्ताओं और पूंजीपतियों की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा रहा है। अपने अधिकारों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैंकिंग क्षेत्र – निरंतर चुनौतियां : बैंकिंग क्षेत्र को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य समस्या बढ़ते हुए खराब ऋणों की है। दुर्भाग्य से, सरकार समाधान में विश्वास करती है और वसूली में नहीं। बैंक खामोशी से विशाल सजावटी छंटनियों को सहन कर रहे हैं और चूककर्ता दण्ड मुक्ति से बच जाते हैं। सरकार दावा करती है कि उनके शासन में एनपीए कम हुए हैं, लेकिन तथ्य यह है कि हाल में संसद में दिए गए उत्तर के अनुसार, केवल 2018–19 में, रू0 1,72,465 करोड़ की राशि के एनपीए बट्टे खाते डाले गए थे। लेकिन जो भाग्यशाली लाभार्थी हैं, वे छिपे हुए हैं।

पॉल को भुगतान करने के लिए पीटर को लूटना : एक तरफ, कॉरपोरेट चूककर्ताओं और अपराधियों को तमाम रियायतें दी जा रही हैं लेकिन दूसरी तरफ, खराब ऋणों के बोझ को सेवा प्रभारों में बढोतरी करके और जुर्माना शुल्क लगाकर आम जनता के कन्धों पर डाला जा रहा है। जमाराशि पर ब्याज दर कम की जा रही है और इससे आम आदमी आहत है। हमें उनके हित के लिए भी संघर्ष करने की जरूरत है।

एकता और संघर्ष : एकमात्र तरीका : इस परिदृश्य में, हमारे लिए एक होने और संघर्ष करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। 8 जनवरी की हड़ताल एक शुरूआत है। हमें अपने संघर्ष को जारी रखने की जरूरत है। बैंकों का विलय, विलंबित वेतन पुनरीक्षण आदि मुद्दे हैं इन पर भी हमें आगामी संघर्षों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। यह हमारा नववर्ष का संकल्प हो।

2020 – एआईबीईए का प्लेटिनम जुबली वर्ष : एआईबीईए में हम सभी के लिए, 2020 खास होगा क्योंकि 20 अप्रैल, 2020 को, हमारा प्रिय एआईबीईए 75 वर्ष को अपनो प्लेटिनम जुबली में प्रवेश करेगा।

आइए आशा और आत्मविश्वास के साथ नववर्ष 2020 का स्वागत करें।

आपका साथी,
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री